REGISTERED No. D (D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 4, 1980/आश्विन 12, 1902
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4, 1980/ASVINA 12, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1980

का०आ० 2606.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के अधिवक्ता श्री जी० एस० बोहिदर को उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में अपीलों तथा उनसे उत्पन्न अन्य मामलों में पेश होने तथा उनका संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[संख्या 225/42/80-ए०वी०डी० (II)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 16th September, 1980

S.O. 2606.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri G. S. Bohider, Advocate, Orissa High Court, Cuttack as Special Public Prosecutor to appear and conduct appeals and other matters arising out of Delhi Special Police Establishment cases in the Orissa High Court, Cuttack.

[No. 225/42/80-AVD. II]

का०आ० 2607.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री डी० सत्यनारायण को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के मामलों में अपीलों तथा उनसे उत्पन्न अन्य मामलों में पेश होने तथा उनका संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 225/42/80-ए०वी०डी० (II)]

S.O. 2607.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri D. Satyanarayan, Advocate, Andhra Pradesh, High Court as Special Public Prosecutor to appear and conduct appeals and other matters arising out of Delhi Special Police Establishment cases in the Andhra Pradesh High Court, Hyderabad.

[No. 225/42/80-AVD. II]

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1980

का०आ० 2608.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, एर्नाकुलम स्थित विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में श्री आर० जे० बसु तथा अन्यों के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 23/70-केरल में अभियोग का संचालन करने तथा उससे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए श्री एम० बी० कुरुप, अधिवक्ता, एर्नाकुलम तथा श्री जोसे के० कोचूपप्पू, अधिवक्ता, एर्नाकुलम को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/55/80-ए०वी०डी० (II)]

New Delhi, the 18th September, 1980

S.O. 2608.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri M. B. Kurup, Advocate, Ernakulam and Shri Jose K. Kochupappu, Advocate, Earnakulam as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution and also any other matter arising out of Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 23/70-KER against Shri R. J. Basu and others in the trial, appellate and revisional courts at Ernakulam.

[No. 225/55/80-AVD. II]

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का०आ० 2609.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा एर्नाकुलम [illegible] विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में श्री आर० मु[illegible] तथा [illegible] विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 1/72-केरल में अभियोजन तथा उससे उत्पन्न किसी अन्य मामले का भी संचालन करने के लिए श्री थामस वी० जैकब, अधिवक्ता, एर्नाकुलम तथा श्री वी० भास्कर मेनन, अधिवक्ता, एर्नाकुलम को विशेष लोक अभियोजक के रूप मे नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/53/80-ए०वी०डी०(II)]

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2609.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri Thomas V. Jacob, Advocate, Ernakulam and Shri V. Bhaskara Menon, Advocate, Ernakulam as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution and also any other matter arising out of Delhi Special Police Establishment Regular Case No. 1/72-KER against Shri R. Muthuswamy and others in the trial, appellate and revisional courts in Ernakulam.

[No. 225/53/80-AVD. II]

का० आ० 2610—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, मैसर्स एगोबीन ट्रेडर्ज, त्रिकारा के प्रबन्ध-साझीदार श्री फ्रेड्रिक मैयने तथा अन्यों के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला संख्या 16/71-केरल में एर्नाकुलम स्थित विचारण, अपीलीय तथा पुनरीक्षण न्यायालयों में अभियोजन तथा उससे उत्पन्न किसी, अन्य मामले का भी संचालन करने के लिये श्री ए० के० श्रीनिवासन, अधिवक्ता, एर्नाकुलम तथा श्री पी० पी० थाम्पी, अधिवक्ता, एर्नाकुलम को विशेष लोक-अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/54/80-ए०वी०डी० (II)]

ज्ञान प्रकाश कालड़ा, अवर सचिव

S.O. 2610.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) the Central Government hereby appoints Shri A. K. Sreenivasan, Advocate Ernakulam and Shri P. P. Thampi, Advocate, Ernakulam as Special Public Prosecutors for conducting the prosecution and also any other matter arising out of Delhi Special Police Establishment Regular case No. 16/71-KER against Shri Frederick Nayne, Managing Partner M/s. Agobin Trades, Trikkara and others in the trial appellate and revisional courts in Ernakulam.

[No. 225/54/80-AVD-II]

G. P. KALRA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1980

का०आ० 2611—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) के अनुसरण में, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन (प्रथम संशोधन) नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 की अनुसूची 7 में "मोटर यानों और मोटर साइकिलों का निष्प्रयोज्य ठहराया जाना" शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
"मोटर यानों और मोटर साइकिलों का निष्प्रयोज्य ठहराया जाना" ।	केन्द्रीय सरकार के विभाग	1 लाख रु० वह शक्ति निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्रयोग की जा सकेगी अर्थात् :— (क) चलाई गई दूरी (किलोमीटरों मे) और प्रयोग की

1	2	3
		अवधि (वर्षों में) जो भी देर से आए, के अर्थ में विभिन्न प्रकार के यानों का जीवन निम्नलिखित रूप में नियत किया गया है ।
		यानों की किस्म — किलोमीटर — वर्ष
		(i) भारी वाणिज्यिक मोटर यान — 3,00,000 — 8
		(ii) मोटर यान जिनमें 18 अश्व शक्ति (आइ० ए० सी०) से कम का इंजन लगा है । — 1,50,000 — 8
		(iii) मोटर साइकिलें जिनमें 3.5 अश्व शक्ति (आर० ए० सी०) या अधिक वाले इंजन लगे हैं । — 80,000 — 5
		(iv) मोटर साइकिलें जिनमें 3.5 अश्व शक्ति (आर०ए० सी०) से कम वाले इंजन लगे हैं । — 60,000 — 5
		(ख) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई यान तभी निष्प्रयोज्य ठहराया जाना चाहिए जब कि नगर विमानन विभाग या दिल्ली परिवहन निगम के विद्युत और यांत्रिकी अधिकारी से केन्द्रीय सरकार के विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि यान का आगे उपयोग करना मितव्ययिता की दृष्टि से ठीक नहीं है । दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के बाहर के स्थानों पर किसी यान को निष्प्रयोज्य ठहराने के लिए किसी समरूप तकनीकी अधिकारी से पूर्वोक्त रूप में प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होगा ।"

[सं० फा० 1(4)/ई-II(ए)/80]

एस० के० दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 4th September, 1980

S.O. 2611.—In pursuance of clause (3) of article 77 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Delegation of Financial Powers (First Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, in Schedule VII, for the entry "Condemnation of motor vehicles and motor cycles", and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3
"Condemnation of motor vehicles and moter cycles.	Departments of the Central Government.	Rs. 1 lakh—This power may be exercised subject to the following restrictions, namely :— (a) the lives of various types of vehicles, in terms of distance run (in kilometers) and length of use (in years) whichever is reached later, have been fixed as under :—

Type of vehicles.	Kilometers	years
(i) Heavy Commercial motor vehicles.	3,00,000	8
(ii) Motor vehicles fitted with less than 18 H.P. (RAC).	1,50,000	8
(iii) Motor cycles fitted with engines of 3.5 H.P. (RAC) or above.	80,000	5
(iv) Motor cycles fitted with engines of less than 3.5 H.P. (RAC).	60,000	5

(b) A vehicle in the Union territory of Delhi should be condemned only after a certificate has been obtained by the Department of the Central Government directly from the Electrical and Mechanical Officer, Civil Aviation Department or the Delhi Transport

1	2	3
		Corporation to the effect that the vehicle is not fit for any further economical use. At places outside the Union Territory of Delhi, a certificate as aforesaid from a similar technical authority will be necessary for condemning a vehicle."

[No. F. 1 (4)/E-II (A)/80]

S.K. DAS, Under Secy.

(राजस्व एवं बैंकिंग विभाग)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

मदुरई, 18 अगस्त, 1980

सीमा शुल्क नीति

का० आ० 2612—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 (ए) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टूटीकोरिन पोर्ट के उत्तरी बांध पर स्थित तेल जट्टी को नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार, निर्यात एवं आयात कार्यों के लदाने और उतारने के लिए उचित स्थान के रूप में, मै घोषित करता हूं ।

तेल जट्टी का परिमाण निम्नलिखित है :—

लम्बाई : अधिकतम 228 मीटर : न्यूनतम 150 मीटर

चौड़ाई : 27.5 मीटर

गहराई : 10.1 मीटर

सीमाएं :

उत्तर : बंगाल की खाड़ी

दक्षिण : बंगाल की खाड़ी से पार दक्षिण बांध

पश्चिम : सुरक्षा दीवार

पूर्व : बंगाल की खाड़ी

[अधिसूचना सं० 2/80/सी० सं० VIII/40/3/80-सीमाशुल्क-I]

आर० जयरामन, समाहर्ता

(Department of Revenue and Banking)

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

Madurai, the 18th August, 1980

CUSTOMS POLICY

S.O. 2612.—In exercise of the powers vested under section 8(a) of the Customs Act, 1962 I declare OIL JETTY LOCATED IN NORTH BREAKWATER AT TUTICORIN PORT as per details below as proper place for loading and unloading of export and import cargo.

The dimension of the oil jetty is as follows :—

Length : Max. 228 Mts. Min. 150 Mts.

Width : 27.5 Mts

Depth : 10.1 Mts

BOUNDARIES :

North : Bay of Bengal

South : South Breakwater beyond that of Bay of Bengal.

West : Security wall.

East : Bay of Bengal.

[Notification No. 2/80/C. No.VIII/40/3/80-CUS. I]

R. JAYARAMAN, Collector

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1980

बीमा प्रभाग

का०आ० 2613.--दिनांक 30 अगस्त, 1980 की इस मंत्रालय की अधिसूचना के सिलसिले में और जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी० दीक्षित को निगम के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से उस पद पर कार्य करते रहने की तारीख तक भारतीय जीवन बीमा निगम बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।

[एफ० संख्या 124 (11) बीमा IV/80]

शिव दयाल रहेजा, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th September, 1980

INSURANCE DIVISION

S.O. 2613.—In continuation of this Ministry's Notification dated 30th August, 1980 and in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri V. Dixit, as member of the Board of Life Insurance Corporation of India from the day he takes over as Managing Director of the Corporation till he holds charge of the said post.

[F. No. 124(11) Ins. IV/80]

S. D. RAHEJA, Under Secy.

आयकर आयुक्त का कार्यालय, विदर्भ

नागपुर, 8 अगस्त, 1980

का०आ० 2614.—नीचे दी गई सूची में वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान निर्धारितियों के नाम और अन्य विवरण दिखाए गए हैं । इस सूची की अनुसूची-1 में ऐसे व्यष्टि (इन्डीविजुअल) और हिन्दू अविभक्त परिवार (एच०यू०एफ०) जिनकी आय 2 लाख रुपयों से अधिक निर्धारित की गई है, उन्हें दिखाया गया है और अनुसूची-II में ऐसी फर्में, व्यक्ति समुदाय (ए०ओ०पी) और कम्पनियां जिनकी आय 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है, दिखाया गया है । इनमे (i) में हैसियत (स्टेटस) व्यष्टि को "व्य" हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए "हिअप" पंजीकृत फ' के लिए "पफ" व्यक्ति समुदाय के लिए "व्यस" और कम्पनियों के लिए "क" से इंगित किया गया है, और (ii) में निर्धारण वर्ष (iii) में विवरणी में दर्शायी गई आय, (iv) में निर्धारित आय, (v) में

देय कर, (vi) में निर्धारिती द्वारा अदा किया गया कर बताया गया है :—

अनुसूची-I

1. श्री गुलाबदास रामबिलास अग्रवाल, रामदासपेठ, नागपुर । (i) व्य (ii) 1975-76 (iii) रु० 4493 (iv) रु० 4,45,252 (v) रु० 3,57,780 (vi) कुछ नहीं ।

2 श्री हाजी वली मोहम्मद, नागपुर—(i) व्य (ii) 1977-78 (iii) रु० 2,20,701 (iv) रु० 2,28,770 (v) रु० 1,25,697 (vi) रु० 1,25,697

3 श्री हाजी सत्तार, द्वारा मैसर्स हाजी लतीफ गनी, कच्छी, नागपुर । (i) व्य (ii) 1977-78 (iii) रु० 2,28,830 (iv) रु० 2,38,390 (v) रु० 1,31,632 (vi) रु० 1,31,632

4 श्री हाजी गफार, द्वारा मैसर्स हाजी लतीफ गनी कच्छी, नागपुर । (i) व्य (ii) 1977-78 (iii) रु० 2,24,650 (iv) रु० 2,33,320 (v) रु० 1,28,286 (vi) रु० 1,28,286

5. श्री असगर अली हसन अली, इतवारी, नागपुर —(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) रु० 3,18,700 (iv) रु० 3,17,440 (v) रु० 1,95,892 (vi) रु० 1,95,892

6 श्री अब्दुल्लाभाई हसन अली, इतवारी, नागपुर—(i) व्य (ii) 1979-80 (iii) रु० 3,56,890 (iv) रु० 3,55,630 (v) रु० 2,20,951 (vi) रु० 2,20,951 ।

7. श्री एच० एल० मुलतानी, भागीदार मैसर्स अलाइड इलैक्ट्रिक स्टोर्स, नागपुर—(i) व्य (ii) 1978-79 (iii) रु० 2,12,270 (iv) रु० 2,15,180 (v) रु० 1,24,554 (vi) रु० 1,29,467

अनुसूची-II

1. मैसर्स अब्दुल हुसेन एम० अल्लाबक्सजी, नागपुर—(i) पफ (ii) 1978-79 (iii) रु० 11,08,050 (iv) रु० 11,03,404 (v) रु० 2,88,439 (vi) रु० 2,88,439

[फा०सं० तक०/287/42-ए/79-80]

Office of the Commissioner of Income-tax, Vidarbha

Nagpur, the 8th August, 1980

S.O. 2614—Following is the list of the names and other particulars of the assessees namely Individuals and HUFs assessed on an income over Rs. 2 lakhs in Schedule I, and Firms, A.O.Ps. and Companies assessed on an income over Rs. 10 lakhs in Schedule II, during the Financial year 1979-80. (i) Indicates status 'I' for Individuals, 'H' for Hindu Undivided Families, 'R.F.' for Registered Firms, 'AOP' for Association of Persons and Co., for Companies; (ii) for assessment year ; (iii) for Income returned, (iv) for income assessed ; (v) for tax payable ; (vi) for tax paid by the assessee :

SCHEDULE—I

1. Shri Gulabdas Rambilas Agrawal, Ramdaspeth, Nagpur. (i) I (ii) 1975-76 (iii) Rs. 4493 (iv) Rs. 4,45,252 (v) Rs. 3,57,780 (vi) Nil.

2. Shri Haji Wali Mohd., Nagpur. (i) I (ii) 1977-78 (iii) 2,20,701 (iv) Rs. 2,28,770 (v) Rs. 1,25,697 (vi) Rs. 1,25, 697.

3. Shri Haji Sattar c/o M/s. Haji Latif Gani, Kachha, Nagpur (i) I (ii) 1977-78 (iii) Rs. 2,28,830 (iv) Rs. 2,38,390 (v) Rs. 1,31,632 (vi) Rs. 1,31,632.

4. Shri Haji Gaffar, C/o M/s. Haji Latif Gani Kachhi Nagpur. (i) I (ii) 1977-78 (iii) Rs. 2,24,650 (iv) Rs. 2 33,320 (v) 1,28,286 (vi) Rs. 1,28,286

5. Shri Asgarali Hasanali, Itwari, Nagpur. (i) I (ii) 1979-80 (iii) Rs. 3,18,700 (iv) Rs. 3,17,440 (v) Rs. 1,95,892 (vi) Rs. 1,95,892.

6. Shri Abdullabhai Hasanali, Itwari, Nagpur. (i) I (ii) 1979-80 (iii) Rs. 3,56,890 (iv) 3,55,630 (v) Rs 2,20,951 (vi) Rs. 2,20,951.

7. Shri H.L. Multani, P/o M/s. Allied Elec. Stores, Nagpur. (i) I (ii) 1978-79 (iii) Rs. 2,12,270 (iv) Rs. 2,15,180 (v) Rs. 1,24, 554 (vi) Rs. 1,29,467.

SCHEDULE—II

1. M/s. Abdul Hussain M. Allabuxji, Nagpur. (i) RF (ii) 1978-79 (iii) Rs. 11,08,050 (iv) Rs. 11,03,404 (v) Rs. 2,88,439 (vi) Rs. 2,88,439.

[F. No. Tech./287/42-A-/79-80]

का० आ० 2615—नीचे दी गई सूची में वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान जिन व्यक्तियों पर कम से कम रुपए 5,000 की शास्ति (पेनाल्टी) लगाई गई थी, उनके नाम दिखाए गए हैं। इनमें (1) में हैसियत (स्टेटस) व्यष्टि के लिए "व्य", हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए "हिअप", पंजीकृत फर्म के लिए "पफ", अपंजीकृत फर्म के लिए "अपफ" कम्पनी के लिए "क" और सहकारी समिति (को-आपरेटिव सोसायटी) के लिए "सम", व्यक्ति समुदाय के लिए "व्यस" से इंगित किया गया है और (2) में निर्धारण वर्ष (3) में शास्ति (पेनल्टी) की रकम (4) में धारा जिसके अन्तर्गत शास्ति लगाई गई थी, दिखाए गए हैं :—

1. श्री जी० के० बुटी, नागपुर. (1) व्य (2) 1974-75 (3) रु० 31,000 (4) 18(1)(सी)

2. श्री बी० पी० बुटी, नागपुर : (1) व्य (2) 1971-72 (3) रु० 30,073 (4) 18(1)(सी)

3. श्रीमती इंदिरा बाई बुटी, नागपुर : (1) व्य (2) 1974-75 (3) रु० 24,489 (4) 18(1)(ए)

4 श्रीमती इंदिरा बाई बुटी, नागपुर : (1) व्य (2) 1973-74 (3) रु० 18,876 (4) 18(1)(ए)

5. श्रीमती इंदिरा बाई बुटी, नागपुर : (1) व्य (2) 1973-74 (3) रु० 42,987 (4) 18(1)(सी)

6. श्रीमती इंदिरा बाई बुटी, नागपुर : (1) व्य (2) 1974-75 (3) रु० 86,292 (4) 18(1)(सी)

7. श्री एम० पी० बुटी, नागपुर. (1) हिअप (2) 1971-72 (3) रु० 1,30,100 (4) 18(1)(सी)

8. श्री एम० पी० बुटी, नागपुर. (1) हिअप (2) 1972-73 (3) रु० 1,61,280 (4) 18(1)(सी)

9. श्री एम० पी० बुटी, नागपुर : (1) हिअप (2) 1973-74 (3) रु० 1,15,960 (4) 18(1)(सी)

10. श्री एम० पी० बुटी, नागपुर : (1) हिअप (2) 1973-74 (3) रु० 8,058 (4) 18(1)(ए)

11 श्री एम० पी० बुटी, नागपुर : (1) हिअप (2) 1974-75 (3) रु० 6,326 (4) 18(1)(ए)

12. मैसर्स पंजाब मिल्स स्टोर्स, नागपुर : (1) पफ (2) 1974-75 (3) रु० 10,875 (4) 271(1)(ए)

13. मैसर्स पंजाब मिल्स स्टोर्स, नागपुर : (1) पफ (2) 1973-74 (3) रु० 20,035 (4) 271(1)(ए)

14. मैसर्स पावर ब्रदर्स, पुलगांव : (1) पफ (2) 1973-74 (3) रु० 9,736 (4) 271(1)(ए)

15. मैसर्स नवलचंद प्रतापचंद, वर्धा : (1) पफ (2) 1975-76 (3) रु० 5,354 (4) 271(1)(ए)

16 मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर : (1) व्यस (2) 1958-59 (3) रु० 27,000 (4) 271 (1)(सी)

17. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर : (1) व्यस (2) 1959-60 (3) रु० 41,000 (4) 271 (1)(सी)

18. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर (1) व्यस (2) 1960-61 (3) रु० 8,000 (4) 271 (1)(सी)

19. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर : (1) व्यस (2) 1961-62 (3) रु० 21,000 (4) 271 (1)(सी)

20. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर (1) व्यस (2) 1962-63 (3) रु० 10,000 (4) 271 (1)(सी)

21. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर (1) व्यस (2) 1964-65 (3) रु० 13,000 (4) 271 (1)(सी)

22. मैसर्स किमतराम राधाकिसन एण्ड कम्पनी, इतवारी, नागपुर : (1) व्यस (2) 1964-65 (3) रु० 15,672 (4) 271 (1)(ए)

23. मैसर्स रोशनलाल एण्ड कम्पनी अमरावती : (1) पफ (2) 1974-75 (3) रु० 25,504 (4) 271(1)(सी)

24. श्री नन्दलाल सूरजमल खेतान, बनोसा, जि० अमरावती : (1) व्य (2) 1968-69 (3) रु० 9,881 (4) 271(1)(ए)

[फा० सं० तक०/287/42-ए/79-80]

S.O.2615—Following is the list of persons on whom penalty not less than Rs. 5,000/- was imposed during the financial year 1979-80. (i) Indicating Status 'I' for Individual, 'H' for H.U.F. 'RF' for Registered Firm. 'URF' for Un-Registered firm, 'Co.' for Companies and 'STY' for Co-operative Society, 'AOP' for Association of Persons, (ii) for assessment year (iii) amount of penalty (iv) Section under which penalty was imposed :

1.	Shri G.K. Buty, Nagpur.	(i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. 31,000 (iv) 18 (1)(c)
2.	,, V.P. Buty, Nagpur	(i) I (ii) 1971-72 (iii) Rs. 30,073 (iv) 18 (1)(c)
3.	Smt. Indirabai Buty, Nagpur	(i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. 24,489 (iv) 18 (1)(a)
4.	-do-	(i) I (ii) 1973-74 (iii) Rs. 18,876 (iv) 18 (1)(a)
5.	-do-	(i) I (ii) 1973-74 (iii) Rs. 42,987 (iv) 18 (1)(c)
6.	-do-	(i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. 86,292 (iv) 18 (1)(c)
7.	Shri M.P. Buty,Nagpur	(i) H (ii) 1971-72 (iii) Rs. 1,30,100 (iv) 18 (1)(c)
8.	Shri M.P. Buty Nagpur	(i) H (ii) 1972--73 (iii) Rs. 1,61,280 (iv) 18 (1) (c)
9.	-do-	(i) H (ii) 1973-74 (iii) Rs. 1,15,960 (iv) 18 (1)(c)
10.	-do-	(i) H (ii) 1973-74 (iii) Rs. 8,058 (iv) 18 (1)(a)
11.	-do-	(i) H (ii) 1974-75 (iii) Rs. 6,326 (iv) 18 (1)(a)
12.	M/s. Punjab Mills Stores, Nagpur.	(i) RF (ii) 1974-75 (iii) Rs. 10,875 (iv) 271 (1) (a).
13.	-do-	(i) RF (ii) 1973-74 (iii) Rs. 20,035 (iv) 271 (1) (a)
14.	M/s. Pawar Bros., Pulgaon	(i) RF (ii) 1973-74 (iii) Rs. 9736 (iv) 271 (1) (a)
15.	M/s. Nawalchand Pratapchand, Wardha.	(i) RF (ii) 1975-76 (iii) Rs. 5354 (iv) 271 (1)(a).
16.	M/s. Kimatram Radhakisan & Co., Itwari, Nagpur.	(i) AOP (ii) 1958-59 (iii) Rs. 27,000 (iv) 271 (1) (c)
17.	-do-	(i) AOP (ii) 1959-60 (iii) Rs. 41,000 (iv) 271 (1) (c)
18.	-do-	(1) AOP (ii) 1960-61 (iii) Rs. 8,000 (iv) 271 (1) (c)
19.	-do-	(i) AOP (ii) 1961-62 (iii) Rs. 21,000 (iv) 271 (1) (c)
20.	-do-	(i) AOP (ii) 1962-63 (iii) Rs. 10,000 (iv) 271 (1)(c)
21.	-do-	(i) AOP (ii) 1964-65 (iii) Rs. 13,000 (iv) 271 (1) (c)
22.	-do-	(i) AOP (ii) 1964-65 (iii) Rs. 15,672 (iv) 271 (1) (a)
23.	M/s. Roshanlal & Co., Amravati.	(i) RF (ii) 1974-75 (iii) Rs. 25,504 (iv) 271 (1) (c)
24.	Shri Nandlal Surajmal Khetan, Banosa, Dist. Amravati.	(i) I (ii) 1968-69 (iii) Rs. 9,881 (iv) 271 (1) (a)

[F. No. Tech./287/42-A/79-80]

का० आ० 2616:— वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान रुपए 10 लाख से अधिक के शुद्ध धन (नेट वेल्थ) पर जिन व्यक्तियों का निर्धारण हुआ है, उनकी सूची नीचे दी गई है। (संकेत) (1) में हैसियत (स्टेट्स) व्यष्टि (इंडीविजुअल) के लिए "व्य" और हिन्दू अविभक्त परिवार (एच० यू० एफ०) के लिए "हअप" (2) निर्धारण वर्ष (3) विवरणी में दर्शाया गया धन/निर्धारित धन (4) निर्धारिती द्वारा देय कर (5) निर्धारिती द्वारा अदा किया गया कर :—

1. श्री नवाबखान सिब्बुखान, पिली हवेली, कामठी : (1) व्य (2) 1974-75 (3) रु० 72,000/रु० 13,37,070 (4) रु० 25,112 (5) कुछ नहीं

2. श्री नवाबखान सिब्बुखान, पिली हवेली, कामठी : (1) व्य (2) 1975-76 (3) विवरणी नहीं/रु० 13,65,385 (4) रु० 34,615 (5) —

3. श्री अब्दुल्ला भाई हसन अली, नागपुर (1) व्य (2) 1976-77 (3) रु० 11,11,171/रु० 11,11,171 (4) रु० 23,507 (5) रु० 23,507

4. श्री अब्दुल्ला भाई हसन अली, नागपुर. (1) व्य (2) 1977-78 (3) 11,89,627/रु० 11,89,627 (4) रु० 18,027 (5) रु० 18,027

5. श्री अब्दुल्ला भाई हसन अली, नागपुर (1) व्य (2) 1978-79 (3) रु० 13,10,986/रु० 13,10,986 (4) रु० 20,988 (5) 20,988

6. श्री अब्दुल्ला भाई हसन अली नागपुर : (1) व्य (2) 1979-80 (3) रु० 14 20,413/रु० 14,48 413 (4) रु० 24,350 (5) रु० 24 350

7. श्री असगर अली हसन अली, नागपुर : (1) व्य (2) 1979-80 (3) रु० 12,33,669/ रु० 12,61,700 (4) रु० 17,790 (5) रु० 17,790

8. श्री प्यारचंद केसरीमल पोरवाल, कामठी : (1) हिअप (2) 1975-76 (3) (—) रु० 10,953/रु० 22,38,666 (4) रु० 1,33,166 (5) रु० कुछ नहीं

9 आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग नागपुर : (1) व्य (2) 1967-68 (3) रु० कुछ नहीं/रु० 17,93,000 (4) रु० 23,420 (5) कुछ नहीं

10 आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग, नागपुर. (1) व्य (2) 1968-69 (3) रु० कुछ नहीं/ रु० 18,21,600 (4) रु० 24,080 (5) कुछ नहीं

11. आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग, नागपुर : (1) व्य (2) 1969-70 (3) रु० कुछ नहीं/रु० 19,36,800 (4) रु० 30,850 (5) कुछ नहीं

12. आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग, नागपुर : (1) व्य (2) 1970-71 (3) रु० कुछ नहीं/रु० 22,21,300 (4) रु० 41,500 (5) रु० कुछ नहीं

13. आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग, नागपुर : (1) व्य (2) 1971-72 (3) रु० कुछ नहीं/रु० 22,34,900 (4) रु० 1,05,100 (5) रु० कुछ नहीं

14 आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग, नागपुर (1) व्य (2) 1972-73 (3) रु० कुछ नहीं/ रु० 12,33,900 (4) रु० 32,470 (5) रु० कुछ नहीं

15. आर० एस० एस० केन्द्रीय अर्थ विभाग नागपुर (1) व्य (2) 1974-75 (3) रु० कुछ नहीं/ रु० 10,55,300 (4) रु० 39,325 (5) रु० कुछ नहीं

16 डा० केशवेश्वर भवन स्मारक समिति नागपुर (1) व्य (2) 1975-76 (3) कुछ नहीं/रु० 11 97,700 (4) रु० 61,920 (5) रु० कुछ नहीं

17 श्रीमती लीलाबाई बुटी सीताबर्डी, नागपुर ; (1) व्य (2) 1970-71 (3) रु० 10,07,100/रु० 10,07,100 (4) रु० 7,177 (5) रु० कुछ नहीं

18 श्री आर० एन० आम्बेकर, सिविल लाइन्स, वर्धा (1) हिअप (2) 1975-76 (3) रु० 9 40,500/रु० 10,46,600 (4) रु० 21,864 (5) रु० 21 864

19. श्रीमती बजाज रूपरानी, वर्धा (1) व्य (2) 1975-76 (3) रु० 11,57,600/रु० 11,62,400 (4) रु० 26,495 (5) रु० 26,495

20. श्री गिरधरदास मोहता, हिंगणघाट. (1) व्य (2) 1976-77 (3) रु० 11,05,100/रु० 11,06,000 (4) रु० 24,240 (5) रु० 24,240

21. श्री गिरधरदास मोहता, हिंगणघाट : (1) व्य (2) 1977-78 (3) रु० 12,05,700/रु० 12,01,000 (4) रु० 18,750 (5) रु० 18,750

22. श्री नीरज कुमार बजाज, वर्धा : (1) व्य (2) 1975-76 (3) रु० 11,57,100/रु० 11,57,100 (4) रु० 76,560 (5) 76,560

23. श्री नीरज कुमार बजाज, वर्धा. (1) व्य (2) 1976-77 (3) रु० 21,91,100/रु० 21,91,100 (4) रु० 95,282 (5) रु० 95,282

24. श्री नीरज कुमार बजाज, वर्धा : (1) व्य (2) 1977-78 (3) रु० 29,54,900/रु० 29,54,900 (4) रु० 77,173 (5) रु० 77,173

25. श्री राहुल कुमार बजाज, वर्धा : (1) हिअप (2) 1977-78 (3) रु० 15,30,100/रु० 15,30,100 (4) रु० 39,810 (5) रु० 39,810

26. श्रीमती उमादेवी अग्रवाल, वर्धा : (1) व्य (2) 1977-78 (3) रु० 12,83,700/रु० 12,83,700 (4) रु० 20,844 (5) रु० 20,844

27 श्रीमती जानकी देवी बजाज, वर्धा. (1) व्य (2) 1978-79 (3) रु० 12,20,500/रु० 12,20,500 (4) रु० 19,263 (5) रु० 19,263

[फा० सं० तक०/287/42-ए/79-80]
डी० सी० अग्रवाल, आयकर आयुक्त

S.O. 2616—Following is the list of persons who have been assessed to net wealth over Rs. 10 lakhs during the financial year 1979-80, (indication) (i) Status 'I' for Individuals and 'H' for HUF (ii) Assessment year (iii) For wealth returned/wealth assessed (iv) For tax payable by the assessees (v) Tax paid by the assessees :

1.	Shri Nawabkhan Sibbukhan Pilihaweli, Kamptee.	(i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. 72,000/ Rs. 13,37,070 (iv) Rs. 25,112 (v) Nil
2.	-do-	(i) I (ii) 1975-76 (iii) No return/ Rs. 13,65,385 (iv) Rs. 34,615 (v) — —
3.	Shri Abdulhobhai Hasanali, Nagpur.	(i) I (ii) 1976-77 (iii) Rs. 11,11,171/ Rs. 11,11,171 (iv) Rs. 23,507 (v) Rs. 23,507
4.	-do-	(i) I (ii) 1977-78 Rs. 11,89,627/ Rs. 11,89,627 (iv) Rs. 18,027 (v) Rs. 18,027
5.	-do-	(i) I (ii) 1978-77 (iii) Rs. 13,10,986/ Rs. 13,10,986 (iv) Rs. 20,988 (v) Rs. 20,988
6.	-do-	(i) I (ii) 1979-80 (iii) Rs. 14,20,413/ Rs. 14,48,413, (iv) Rs. 21,350. (v) Rs. 24,350
7.	Shri Asgarali Hasanali, Nagpur	(i) I (ii) 1979-80 (iii) Rs. 12,33,669/ Rs. 12,61,700 (iv) Rs. 17, 90 (v) Rs. 17,790
8.	Shri Pyarchand Keshrimal Porwal, Kamptee.	(i) HUF (ii) 1975-76 (iii) (—) Rs. 10,953/Rs. 22,38,666 (iv) Rs. 1,33,166 (v) Rs. Nil
9.	R.S.S. Kendriya Arth Vibhag, Nagpur	(i) I (ii) 1967-68 (iii) Rs. Nil/ Rs. 17,93,000 (iv) 23,420 (v) Nil
10.	-do-	(i) I (ii) 1968-69 (iii) Rs. Nil/ Rs. 18,21,600 (iv) Rs. 24,080 (v) Nil

11.	R.S.S. Kendriya Karyalaya Vibhag, Nagpur	(i) I (ii) 1969-70 (iii) Rs. Nil/ Rs. 19,36,800 (iv) Rs. 30,850 (v) Rs. Nil
12.	-do-	(i) I (ii) 1970-71 (iii) Rs. Nil/ Rs. 22,21,300 (iv) Rs. 41,500 (v) Rs. Nil
13.	-do-	(i) I (ii) 1971-72 (iii) Rs. Nil/ Rs. 27,34,900 (iv) Rs. 1,05,100 (v) Rs. Nil
14.	-do-	(i) I (ii) 1972-73 (iii) Rs. Nil/ Rs. 12,33,900 (iv) Rs. 32,470 (v) Rs. Nil
15.	-do-	(i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. Nil/ Rs. 10,55,300 (iv) Rs. 39,320 (v) Rs. Nil
16.	Dr. Hedgewar Bhawan Smarak Samiti, Nagpur.	(i) I (ii) 1975-76 (iii) Rs. Nil/ Rs. 11,97,700 (iv) Rs. 61,920 (v) Rs. Nil
17.	Smt. Lilabai Buty, Sitabudi, Nagpur.	(i) I (ii) 1970-71 (iii) Rs. 10,07,100/ Rs. 10,07,100 (iv) Rs. 7,177 (v) Rs. Nil
18.	Shri R.H. Astekar, Civil Lines, Wardha.	(i) HUF (ii) 1975-76 (iii) Rs. 9,40,500/Rs. 10,46,600 (iv) Rs. 21,864 (v) Rs. 21,864
19.	Smt. Bajaj Ruprani, Wardha.	(i) I (ii) 1975-76 (iii) Rs. 11,57,600/ Rs. 11,62,400 (iv) 26,495 (v) Rs. 26,195
20.	Shri Girdhardas Mohota, Hinganghat.	(i) I (ii) 1976-77 (iii) Rs. 11,05,100/ Rs. 11,06,000 (iv) Rs. 24,240 (v) Rs. 24,240
21.	-do-	(i) I (ii) 1977-78 (iii) Rs. 12,05,700/ Rs. 12,01,000 (iv) Rs. 18,750 (v) Rs. 18,750
22.	Shri Nirajkumar Bajaj, Wardha.	(i) I (ii) 1975-76 (iii) Rs. 11,57,100/ Rs. 11,57,100 (iv) 76,560 (v) Rs. 76,560
23.	-do-	(i) I (ii) 1976-77 (iii) Rs. 21,91,100/ Rs. 21,91,100 (iv) Rs. 95,282 (v) Rs. 95,282
24.	-do-	(i) I (ii) 1977-78 (iii) Rs. 29,54,900/ Rs. 29,54,900 (iv) Rs. 77,173 (v) Rs. 77,173
25.	Shri Rahulkumar Bajaj, Wardha.	(i) HUF (ii) 1977-78 (iii) Rs. 15,30,100/ Rs. 15,30,300 (iv) Rs. 39,810 (v) Rs. 39,810
26.	Smt. Umadevi Agrawal, Wardha.	(i) I (ii) 1977-78 (iii) Rs. 12,83,700/ Rs. 12,83,700 (iv) Rs. 20,844 (v) Rs. 20,844
27.	Smt. Jankidevi Bajaj, Wardha.	(i) I (ii) 1978-79 (iii) Rs. 12,20,500/ Rs. 12,20,500 (iv) Rs. 19,263 (v) Rs. 19,263

[F. No. Tech./287/42-A/79-80]

D. C. AGGARWAL, Commissioner of Income Tax

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय

कलकत्ता, 26 जुलाई, 1980

का० आ० 2617.— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944, नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, कलकत्ता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-ए, उपनियम (3) की धारा (VI ए) की उपधारा (ब) के अन्तर्गत की शक्तियों को प्रयुक्त करने को प्राधिकृत करता हूँ।

[अधिसूचना सं० 3/1980/सी० सं० IV(8) 1-के० उ०/78]

बी० एन० रंगवानी, समाहर्ता

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Calcutta, the 26th July, 1980

S.O. 2617.—In exercise of the powers conferred on me by rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, authorise the Assistant Collector of Central Excise, Calcutta, to exercise the power of the Collector of Central Excise, Calcutta, under Sub-clause (d) in clause (VIa) of Sub-rule (3) of Rule 56A of the Central Excise Rules, 1944.

[Notification No. 3/1980/C No. IV(8)1-CE/78]

B. N. RANGWANI, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1980

का० आ० 2618.— इलायची नियम, 1966 के नियम 5 के साथ पठित इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि सर्वश्री जेवियर अराकल तथा वी० एस० विजयराघवन को, जो दोनों लोक सभा के सदस्य है, लोक सभा द्वारा इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया है और विनिर्दिष्ट करती है कि श्री जेवियर अराकल तथा श्री वी० एस० विजयराघवन इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तथा 1 जून, 1981 तक अथवा तब तक के लिए जब तक वे लोक सभा के सदस्य बने रहते हैं, जो भी पहले हो, बोर्ड के सदस्यों के रूप में पद धारण किए रहेंगे।

[फा० सं० 32/10/80-प्लांट (बी)]

एस० महादेव अय्यर, उप निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 16th September, 1980

S.O. 2618—In pursuance of clause (c) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), read with rule 5 of the Cardamom Rules, 1966, the Central Government hereby notifies that Sarvashri Xavier Arakal and V. S. Vijayaraghavan, Members of Lok Sabha have been elected by the Lok Sabha as members of the Cardamom Board and specifies that Shri Xavier Arakal and Shri V. S. Vijayaraghavan shall hold office as members of the Board with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and upto the 4th June, 1981, or until they cease to be members of the Lok Sabha, whichever is earlier.

[F. No. 32/10/80-Plant (B)]

S. MAHADEVA IYER, Dy. Director

(वस्त्र विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1980

का० आ० 2619 — केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्ट सिल्क वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आर्ट सिल्क वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1980 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. आर्ट सिल्क वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 के खण्ड 4 में—

(1) शीर्षक के स्थान पर "कीमतें नियत करना, पैकिंग और चिह्नांकन का विनिर्देश" शीर्षक रखा जाएगा ;

(2) उपखण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2 वस्त्र आयुक्त, आर्ट सिल्क सूत के पैकिंग की रीति, आर्ट सिल्क सूत के विनिर्माता या व्यौहारी द्वारा विनिर्मित या, यथास्थिति, विक्रीत आर्ट सिल्क सूत के किसी वर्ग या विनिर्देश पर चिह्नांकन और ऐसे चिह्नांकन का समय और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

(3) उपखण्ड (3) में, "नियत कीमतों से अधिक" शब्दों के स्थान पर "नियत कीमतों से, यदि कोई हो, अधिक" शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 11011/8/80-ए एण्ड एम० एम० टी०]
बी० के० जुटशी, संयुक्त सचिव

(Department of Textile)

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1980

S.O. 2619.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962 namely :—

1. (1) This order may be called the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control (Amendment) Order, 1980.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order 1962, in clause 4—

(i) In clause for heading, the heading "Fixation of prices specification of packing and making" shall be substituted;

(ii) For sub-clause (2) the following sub-clause shall be substituted namely :—

"(2) The Textile Commissioner may specify the manner of packing artsilk yarn, the markings to be made by manufacturer or dealer on any class or specification of artsilk yarn manufactured or as the case may be sold by him and the time and manner of making such markings."

(iii) in sub-clause (3), for the words "in excess of the prices fixed" the words "in excess of the prices, if any fixed" shall be substituted.

[F. No. 11011 8/80/A&MMT]
B. K. ZUTSHI, Jt. Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1980

का० आ० 2620.— सर्वश्री पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि०, पी० ओ० पेट्रोकैमिकल्स, जिला बड़ौदा (गुजरात) को अप्रैल-मार्च 80 अवधि के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अधीन पॉलिएस्टर चिप्स के आयात के लिए 2,74,38,600 रुपए का आयात लाइसेंस सं० आई०/ए०/1084477/सी० एक्स० एम०/77/एच०/79 दिनांक 28-9-79 प्रदान किया गया था।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रति किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए बिना अस्थानस्थ हो गई है और इसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है। फर्म इस बात से सहमत है और वचन देती है कि यदि मूल सीमा-शुल्क प्रति बाद में मिल भी गई तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए वापिस कर दी जाएगी।

3. अपने तर्क के समर्थन में फर्म ने आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1980-81 के अध्याय 15 के पैरा 352 के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० आई०/ए०/1084477 दिनांक 28-9-79 की मूल सीमा-शुल्क प्रति अस्थानस्थ हो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल सीमा-शुल्क प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० पी०/2/79-80/पी० एल० एस० (ए)/जी० एल० एस०]
बी० मलिक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

Office of the Chief Controller of Imports and Exports

ORDER

New Delhi, the 17th September, 1980

S.O. 2620.—M/s. Petrofils Co-operative Ltd. P.O. Petrochemicals, Distt. Baroda (Gujarat) have been granted import licence No. 1|A|1084477|C|XX|77|H|79 dated 28-9-79 for Rs. 2,74,38,600 only for import of Polyester Chips under G.C.A. for April-March 80 period.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Customs Purposes copy of the above licence on the round that the original Customs Purposes copy has been misplaced without having been registered with any Customs Authority and not utilised at all. The firm agrees and undertakes to return the original Customs Purposes copy of the licence if traced later to this office for record.

3. In support of their contention the firm have filed an affidavit as required in Para 352 of Chapter XV of the Hand Book of Import-Export Procedures 1980-81. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. I/A/1084477 dated 28-9-79 has been misplaced and directs that duplicate copy of the Customs Purposes copy of the licence shquld be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy of licence is hereby cancelled.

4. The duplicate copy of the Customs Purposes copy of the import licence is being issued separately.

[No. P/2/79-80/PLS(A)/GLS]
B. MALIK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
For Chief Controller of Imports & Exports

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का० आ० 2621.— केन्द्रीय सरकार, स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अन्तर-राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) की धारा 12 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य को उस राज्य के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसमें या जिसके किसी भाग में मद्यसारिक पान का उपभोग विधि द्वारा साधारणतया प्रतिषिद्ध है।

[फा० सं० 26(1)/आई० टी०/80]

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 20th September, 1980

S.O. 2621.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 2 of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955), the Central Government hereby specifies the State of Rajasthan as being a State in which or any part of which the consumption of alcoholic liquors is generally prohibited by law.

[File. No 26(1)/IT/80]

का० आ० 2622— केन्द्रीय सरकार, स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अन्तर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम 1955 (1955 का 39) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा भी उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि उक्त राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का, जहां तक वे केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी आदेश या नियमों के विरुद्ध है कोई प्रभाव नहीं होगा।

[फा० सं० 26(1)/आई० टी०/80]

यू० आर० कुर्लेकर, उप सचिव

S.O. 2622.—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers to make rules under section 3 of the said Act shall be exercisable also by the State Government of Rajasthan subject to the condition that the rules made by the State Government shall have no effect in so far as they are repugnant to any order or rules made under the said Act by the Central Government.

[F. No. 26(1)/IT/80]

U. R. KURLEKAR, Dy Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1980

का० आ० 2623— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है,

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात	जिला : भरूच	तालुका : हांसोट		
गांव	ब्लोक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
रोहिद	328	0	05	20
	333	0	11	05
	334/ए	0	06	50
	334/बी	0	06	50
	336	0	13	00

[सं० 12016/39/80-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 12th September, 1980

S.O. 2623.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDD to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed thereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. S.D.D. To Motwan-1

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Hansot		
Village	Block No.	Hectare	ARE	Centiare
Rohid	328	0	05	20
	333	0	11	05
	334/A	0	06	50
	334/B	0	06	50
	336	0	13	00

[No. 12016/39/80-Prod.]

का० आ० 2624—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है,

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला : भरूच	तालुका : हांसोट		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआर	ई सेन्टीयर
कुडाद्रा	185	0	09	10
	186/ए, 186/बी	0	05	20

[सं० 12016/40/80-प्रो०-I]

S.O. 2624.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDD to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user herein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. S.D.D. to Motwan I

State : Gujarat	District Bharuch	Taluka : Hansot		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kudadra	185	0	09	10
	186/A, 186/B	0	05	20

[No. 12016/40/80-Prod. I]

का० आ० 2625—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान 1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० एस० डी० डी० से मोटवान-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात	जिला : भरूच	तालुका : हांसोट		
गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआर	ई सेन्टीयर
कठोदरा	93	0	11	70
	149	0	06	50
	122	0	05	20
	122	0	02	60
	116	0	14	30
	117	0	13	00
	115	0	15	60
	114	0	10	40
	112	0	15	60
	99	0	07	80
	101	0	02	60
	100	0	10	40
	87	0	36	40
	86	0	03	90
	84/ए, 84/बी	0	18	20

[सं० 12016/10/80-प्रो०-2]

S.O. 2625.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDD to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCUEDULE

Pipeline from Well No. S.D.D. to Motwan I

State : Gujarat	District : Bharuch	Taluka : Hansot		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Khathodra	93	0	11	70
	149	0	06	50
	122	0	05	20
	122	0	02	60
	116	0	14	30
	117	0	13	00
	115	0	15	60
	114	0	10	40
	112	0	15	60
	99	0	07	80
	101	0	02	60

1	2	3	4	5
	100	0	10	40
	87	0	36	40
	86	0	03	90
	84/A	0	18	20
	84/B	0	18	20

[No. 12016/40/80-Prod. II]

का० आ० 2626—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० एस०एन०एस० से संथाल तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसे आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एस० एन० एस० से संथाल जी० जी० एस०–I तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं०	हेक्टयर	ए आर ई	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
संथाल	622	0	01	20
	624	0	9	36
	635	0	01	32

[सं० 12016/42/80-प्रा०-I]

S.O. 2626.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from SNS to Santhal-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNS to Santhal GGS-I

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Santhal	622	0	01	20
	624	0	9	36
	635	0	01	32

[No. 12016/42/80-Prod. I]

का०आ० 2627.—यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० जे० एन०जी० से जी०जी०एश० जोटाणा-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनसूची

डी० एस० जे० एन० जी० से जी० जी० एस० झुटाना-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाना

गाव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
झुटाना	1493/2	0	06	00

[स० 12016/42/80-प्रो०-II]

S.O. 2627.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JNG to GGS Jotana-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent

Authority Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from DS JNG to GGS Jotana-I

State : Gujarat Distt : Mehsana Taluka : Mehsana

Survey No.	Heact-are	Are	Centi-are
1493/2	0	06	00

[No. 12016/42/80-Prod. II]

का० आ० 2628.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० मोटवान हीडर से सी० टी० एफ० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अत: अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड़, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

मोटवान हीडर से सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात तालुका : अंकलेश्वर जिला : भरुच

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	ए आर	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तेलवा	133	0	16	25
	132	0	4	44
	128	0	23	01
	146	0	7	80
	147	0	22	75
	126	0	17	16
	186	0	20	15
	185	0	14	17
	182	0	9	36
	183	0	10	79
	179	0	15	47
	177	0	16	38
	174	0	13	91
	173	0	24	31
	172	0	14	69
	171	0	14	82
	169	0	1	95

[सं० 12016/43/80-प्रो०-I]

S.O. 2628.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Motwan Header to CTF in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. Motwan Header to CTF

State : Gujarat Taluka : Ankleshwar District : Bharuch

Village	Block No.	Hect-are	Are	Centi-are
Telwa	133	0	16	25
	132	0	4	55
	128	0	23	01
	146	0	7	80
	147	0	22	75
	126	0	17	16
	186	0	20	15
	185	0	14	17
	182	0	9	36
	183	0	10	79
	177	0	15	47
	179	0	16	38
	174	0	13	91
	173	0	24	31
	172	0	14	69
	171	0	14	82
	169	0	1	95

[No. 12016/43/80-Prod. I]

का० आ० 2629.—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० मोटवान हीडर से सी० टी० एफ० तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

मोटवान हीडर से सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात तालुका—अंकलेश्वर जिला—भरुच

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोटवान	100	0	13	00

[सं० 12016/43/80 प्रो०-II]

S.O. 2629.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Motwan Header to CTF in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Motwan Header to CIF

State : Gujarat Taluka : Anakleshwar Distiict : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Motwan	100	0	13	00

[No. 12016/43/80-Prod-II]

का० आ० 2630—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० मोटवान हीडर से सी० टी० एफ० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

मोटवान हीडर से सी० टी० एफ तक पाइप लाइन बिछान के लिए कूप स० राज्य—गुजरात तालुका—अंकलेश्वर पर जिला—भरुच

गाव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
पिलुदरा	224	0	1	30
	198	0	26	39
	219	0	19	11
	220	0	26	0
	234	0	16	25

[सं० 12016/44/80 प्रो०]

S.O. 2630.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Motwan Header, to CTF in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. Motwan Header to CTF

State : Gujarat Taluka : Ankleshwar District : Bharuch

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Piludra	224	0	1	30
	198	0	26	39
	219	0	19	11
	220	0	26	0
	234	0	16	25
	-	0	2	21

[No. 12016/44/80-Prod.)]

का० आ० 2631—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० के-186 से के-181 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड वडोदरा–9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० 186 से के-181 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कलोल

गांव	सर्वे० नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कलोल	775	0	11	55
	774	0	03	60

[सं० 12016/45/80-प्रो०]

S.O. 2631.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of pertroleum from Well No. 186 to K-181 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the dare of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. K.—186 to K—181.

State : Gujarat District :Mehsana Taluka : Kalo

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalol	775	0	17	55
	774	0	03	60

[No. 12016/45/80—Prod.]

का० आ० 2632—यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य मे कूप नं० सी०ए०ई० मे 54 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनो के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधी व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप सं० सी० ए० ई० से डी० एम० 54 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—खम्भात

गाव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टीयर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोडवा	199	0	16	60
	कार्ट ट्रेक	0	02	60
	200	0	06	50
	139	0	4	68
	137	0	13	26
	135	0	19	11
	138	0	3	38
	108	0	17	42
	105/1	0	00	50
	105/2	0	06	50
	104/1	0	04	46
	103	0	00	50
	101/1	0	10	14

[सं० 12016/46/80-प्रो०]

S.O. 2632.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from CAR to 54 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Well No. CAE to D.S. 54

State : Gujarat Taluka : Cambay District : Kaira

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kodva	199	0	15	60
	Cart Track	0	02	60
	200	0	06	50
	139	0	4	68
	137	0	13	26
	135	0	19	11
	138	0	3	38
	108	0	17	42
	105/1	0	00	50
	105/2	0	06	50
	104/1	0	04	46
	103	0	00	50
	101/1	0	10	14

[No. 12016/46/80- Prod.]

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1980

का० आ० 2633—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० धोलका-6 से धोलका-10 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

धोलका—6 से धोलका—10 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : धोलका

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एआरई	सेन्टियर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वौठा	238	0	04	65
	233	0	10	65
	232	0	10	35
	231	0	08	10
	228	0	02	00

[सं० 12016/38/80-प्रो०]

किरन चड्ढा, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 1980

S.O. 2633.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Dholka-6 to Dholka-10 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipe line From Dholka—6 to Dholka—10

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Dholka

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Vautha	238	0	04	65
	233	0	10	65
	232	0	10	35
	231	0	08	10
	228	0	02	00

[No. 12016/38/80-Prod.]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1980

का० आ० 2631 —यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 30 दिसम्बर, 1960 की अधिसूचना सं० एफ 16-18/60-एम I द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए चिकित्सा अर्हता, एम० डी० (म्यूनस्टर) पश्चिम जर्मनी मान्य चिकित्सा अर्हता होगी ;

और यतः डा० (श्रीमती) हिलेडगर्ड सिना जिनके पास उक्त अर्हता है, धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिए फिलहाल मित्रनिकेतन अस्पताल, वेधमान, त्रिवेन्द्रम के साथ सम्बद्ध हैं ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा —

(1) सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की और अवधि, अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० (श्रीमती) हिलेडगर्ड सिना उक्त मित्रनिकेतन अस्पताल, वैधमान, त्रिवेन्द्रम, केरल राज्य के साथ सम्बद्ध रहती हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मेडिकल प्रेक्टिस कर सकेंगे।

[सं० वी० 11016/3/80-एम०ई० (पी)]

के० वेणुगोपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 26th July, 1980

S.O.2634.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. F. 16-18/60-MI, dated 30th December, 1960 the Central Government has directed that the Medical qualification, MD (Muenster) West Germany shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) :

And whereas Dr. (Mrs.) Hildegard Sina, who possesses the said qualification is for the time being attached to the Mitraniketan Hospital, Veghamon, Trivandrum for the purposes of charitable work.

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the provios to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a further period of two years from the date of issue of the 'Order' in the official gazette, or

(ii) the period during which Dr. (Mrs.) Hildegard Sina, is attached to the said Mitraniketan Hospital, Vaghamon, Trivandrum, Kerala State.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/3/80-M.E. (Policy)]

K. VENUGOPAL, Under Secy.

नई दिल्ली 18 सितम्बर, 1980

का० आ० 2635.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 के उप खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आगे और निम्नलिखित संशोधन किया है, नामतः—

उक्त अनुसूची के भाग-1 में अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने "आयुर्वेदाचार्य" की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए अर्थात्—

"आयुर्वेद शास्त्री . . . . . 1974 से आगे"

[संख्या वी० 26011/6/79-ए० ई०]

एच० एस० धकालिया, अवर सचिव

New Delhi, the 18th September, 1980

S.O.2635.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In part I of the said Schedule against serial No. 12 relating to all India Ayurveda Vidyapeeth, Delhi, after the entry "Ayurvedacharya.....", the following entry shall be inserted, namely :—

"Ayurved Shastri..... .From 1974 onwards".

[No. V. 26011/6/79-AE]

H. S. DHAKAALIA, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1980

का० आ० 2636.—डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, विशाखापत्तनम गोदी श्रम बोर्ड के सदस्य श्री के० एस० दत्त की, 9 अगस्त, 1980 को हुई मृत्यु के के फलस्वरूप हुई रिक्ति को अधिसूचित करती है।

[फा० सं० एल० डी० वी०/17/79-एल-III]

चन्द्रभान बडगूजर, निदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 18th September, 1980

S.O.2636.—In pursuance of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the vacancy occurred in the Visakhapatnam Dock Labour Board, by the death of its member, Shri K. S. Dutt, expired on 9th August, 1980.

[F. No. LDV/17/79-L.III]

C. B. BADGUJAR, Director

निर्माण और आवास मंत्रालय

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 2637.—भारत सरकार के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3(i) दिनांक 21 जून, 1980 को पैरा 7 में जी० एस० आर० 673 के अन्तर्गत अधिसूचित इस मन्त्रालय के सचिवालय में डिस्पैच राइडर के भर्ती नियमों में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ा जाय।

"निरस्त" निर्माण और आवास तथा नगर विकास विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 1969 तथा निर्माण और आवास तथा नगर विकास विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 1974 को निरस्त किया जाता है।

[सं० ए० 12028/2/79 प्रशा० 1]

एस० ए० रसल, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

ADDENDUM

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2637.—The following para may be added to the Recruitment Rules for Despatch Rider in the Secretariat of this Ministry notified under GSR 673 in the Gazette of India; Part II, Section 3(i), dated 21st June 1980 as para 7 :—

"Repeal": The Department of Works, Housing and Urban Development (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1969 and the Department of Works, Housing and Urban Development (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1974 are repealed".

[No. A-12028/2/79-Adm. I]
S. A. RUSSELL, Under Secy.

(दिल्ली विकास प्राधिकरण)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1980

का० आ० 2638:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिसे सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इस संशोधन के सम्बन्ध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना अनुभाग, 10वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन .

क्षेत्र एफ-6 (मोती बाग क्षेत्र) में स्थित "मनो विनोद क्षेत्र" (जिला पार्कों खेल के मैदानों एवं खुले स्थानों) में से लगभग 0.85 हक्टे० 2.11 एकड़) क्षेत्रफल का भूमि उपयोग "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं" (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) में संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना अनुभाग), 10वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधन का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं० एफ० 20(13)80-एम० पी०]

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 4th October, 1980

S.O. 2638 —The following modification which the Central Govt. proposes to make to the Master Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan section, 10th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address:

MODIFICATION :

The land use of an area measuring about 0.85 hect. (2.11 acres) situated in zone F-6 (Moti Bagh area) out of the 'recreational' area (district Parks, play grounds and open spaces) is proposed to be changed to 'public and semi-public facilities' (Higher Secondary school).

2. The Plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20 (13) 80-MP]

का० आ० 2639—(ए) दिल्ली मुख्य योजना के क्षेत्र डी-3 [कर्जन रोड क्षेत्र] के क्षेत्रीय विकास चित्र (अधिसूचना सं० 21023 (11) 66-यूडी दिनांक 16-12-66 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित) मे पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में इंगित किए क्षेत्रों हेतु पुनर्विकास प्रस्ताव प्रारूप तैयार हो चुके हैं ।

(बी) उनके पाठ एवं चित्र की एक प्रति दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय मे शनिवार को छोड़कर शेष सभी कार्यशील दिवसों में 11 00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अपराह्न) तक यहां पैरा 3 में उल्लिखित तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

2. एतद्द्वारा इन प्रारूप प्रस्तावों के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित किए जाते हैं ।

3. आपत्तियां एवं सुझाव इस सूचना के जारी किये जाने की तिथि से 30 दिन में सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य योजना अनुभाग 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज दिए जाएं । आपत्ति/सुझाव लिखने वाले व्यक्ति को अपना नाम एवं पूरा पता भी लिखना चाहिए ।

[सं० एफ० 4(24)/63-एम० पी०]

S. O. 2639—(a) The draft redevelopment proposals for zone D-3 (Curzon Road Area) of Delhi Master Plan for the area indicated as redevelopment areas in the zonal Developmet Plan approved by the Central Government vide notification No. 21023 (11) 66-UD dated 16-12-66) have been prepared.

(b) A copy of the text and the plan thereof will be available for inspection in the office of the Delhi Development Authority, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, between the hours of 11.00 a.m. and 3.00 p.m. on all working days except Saturdays till the date mentioned in para 3 hereafter.)

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to these draft proposals.

3. The objections or suggestions may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objections/suggestions should also give his name and full address.

[No. F. 4 (24)/63—MP]

का० आ० 2640:—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास चित्र में निम्नलिखित संशोधनों को करने का विचार कर रही है, एतद्द्वारा जिन्हें सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है । इन संशोधनों के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति या सुझाव इस सूचना के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना अनुभाग, 10वी मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप मे भेज दें । जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दें, वे अपना नाम एवं पूरा पता लिखें ।

संशोधन :

1 "मुख्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में मनोरंजनात्मक' उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि मे लगभग 2.02 हैक्टे० (5 एकड़) क्षेत्रफल, जो शाहपुर जाट गांव के उत्तर मे स्थित है, का भूमि उपयोग 'सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं (सांस्थानिक)' में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

(2.) "मुख्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र में 'मनोरंजनात्मक' उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि में से लगभग 13.14 हैक्ट० (32.36 एकड़) क्षेत्रफल, जो शाहपुर जाट गांव के उत्तर पूर्व मे स्थित है, का भूमि उपयोग 'आवासीय उपयोग (खेलगाव)' मे परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

(3.) "मख्य योजना/क्षेत्र एफ-3 हेतु क्षेत्रीय विकास चित्र मे 'सार्वजनिक एव अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं (सस्थानिक)' उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट भूमि में से लगभग 2.83 हैक्ट० (7 एकड़) क्षेत्रफल जो शाहपुर जाट गांव के पूर्व में स्थित है, का भूमि उपयोग 'आवासीय उपयोग (खेल गांव)' में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है ।"

2. शनिवार को छोड़कर और सभी कार्यशील दिनों में दि० वि० प्रा० के कार्यालय (मुख्य योजना अनुभाग), 10वीं मंजिल, विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि के दौरान प्रस्तावित संशोधनो का मानचित्र निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगा ।

[सं० एफ० 20(6)/79-मु० यो०]
बी० के० मल्होत्रा, सचिव
दिल्ली विकास प्राधिकरण।

S.O. 2640.—The following modifications which the Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan are hereby published for public information. Any person having any objection or sugestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Master Plan Section, 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also given his name and full address:

MODIFICATONS :

(1) "The land use of an area, measuring about 2.02 hects. (5 acres), out of the land carmarked for 'Recreational' use in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the north of village shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Public & Semi-Public Facilities' (Institutional)."

(2) "The land use of an area, measuring about 13.14 hects. (32.36 acres), out of the land earmarked for 'Recreational use in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the north-east of village Shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Residential' use (Sports village)."

(3) "The land use of an area, measuring about 2.83 hects. (7 acres), out of the land earmarked for 'Public & Semi-Public Facilities,' (Institutional) use in the Master Plan/Zonal Development Plan for Zone F-3, located in the east of village Shahpur Jat, is proposed to be changed to 'Residential' use (Sports village)."

2. The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the of office of the Authority (Master Plan Section), 10th Floor, Vikas Minar, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20 (6) /79-MP]
B. K. MALHOTRA Secy.
Delhi Development Authority.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1980

का० आ० 2641.—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सहायक महा अभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए, तत्काल प्रभाव से, सहायक अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

2. इससे अधिसूचना संख्या 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II दिनांक 9-10-1979 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(1):वि०सैल/79-एस० एस० II]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 5th September, 1980

S.O. 2641.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), the Central Government hereby appoints with immediate effect Shri Rajender Nath Sinha, Additional Secretary in the Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act.

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II, dated 9-10-1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS.-II]

का० आ० 2642.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा, बिहार सरकार के राजस्व-व-भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को, अपर सचिव के रूप में उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य में मुआवजा पूल की भूमियों तथा सम्पत्तियों के संबंध में, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

2. इससे अधिसूचना सं० 1(1)/विशेष सेल/79-एस० एस०-II दिनांक 9-10-79 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II]
एन० एम० वाधवानी, अवर सचिव

S.O. 2642.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri Rajender Nath Sinha, Additional Secretary to the Government of Bihar, Revenue and Land Reforms Department, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties as Additional Secretary, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the lands and properties forming part of the Compensation Pool within the State of Bihar.

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS. II., dated 9-10-1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79-SS.II]
N. M. WADHWANI Under Secy.

का० आ० 2643.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, इसके द्वारा, बिहार सरकार के राजस्व तथा भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव, श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा, जिन्हें इस विभाग की अधिसूचना सं० 1(1)/वि०सैल/79-एस० एस०-II दिनांक 5 सितम्बर, 1980 द्वारा बंदोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, को अपनी निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 23 के अधीन अपील सुनने की शक्तियां ।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन पुनरीक्षण सम्बन्धी मामलो की सुनवाई की शक्तियां ।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन मामलो के हस्तांतरण की शक्तियां ।

2 इससे इस विभाग की अधिसूचना सख्या 1(1)/वि०सै०/79-एस० एस०-II दिनाक 9-10-1979 का अतिक्रमण किया जाता है ।

[संख्या 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II]

S.O. 2643.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), I hereby delegate to Shi Rajender Nath Sinha, Additional Secretary to the Government of Bihar, Revenue and L & R Department, appointed as Settlement Commissioner, vide this Department's notification No. 1(1)/Spl. Cell/79-S S.II , dated 5th September, 1980, the following powers:—

(i) Powers to hear appeals under Section 23 of the said Act.

(ii) Powers to hear revisions under Section 24 of the said Act.

(iii) Powers to transfer cases under Section 28 of the said Act

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl Cell/79-SS II , dated 9-10-1979.

[No. 1(1)/Spl. Cell/79.-SS -II]

का० आ० 2644—निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) की धारा 55 की उपधारा (3) द्वारा महाअभिरक्षक के रूप मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मैं, इसके द्वारा, बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव तथा इस विभाग की दिनांक 5 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना स० 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II द्वारा सहायक महाअभिरक्षक नियुक्त सम्पत्ति के रूप मे नियुक्त किए गए श्री राजेन्द्र नाथ सिन्हा को महाअभिरक्षक की निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हू —

(i) उक्त अधिनियम की धारा 24 और 27 के अधीन शक्तियां।

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 10(2)(0) के अधीन किसी भी निष्क्रांत सम्पत्ति के हस्तांतरण के अनुमोदन की शक्तियां ।

(iii) निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 30-क के अधीन मामलो के हस्तांतरण की शक्तिया ।

2 इससे अधिसूचना सं० 1(1)/वि० सैल०/79-एस० एस० II दिनांक 9-10-1979 का अतिक्रमण किया जाता है ।

[स० 1(1)/वि० सैल/79-एस० एस०-II]
गोविन्द जी मिश्र, महाअभिरक्षक

S.O. 2644.—In exercise of the powers conferred on me as Custodian General by Sub-Section (3) of Section 55 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950), I hereby delegate to Shri Rajender Nath Singh, Additional Secretary, in the Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, appointed as Assitant Custodian General of Evacuee Prope ty for the State of Bihar, vide this Department's Notification No 1(1)/Spl. Cell/79-SS.-II., dated the 5th September, 1980, the following powers of the Custodian General .—

(i) Powers under Sections 24 and 27 of the Act.

(ii) Powers of approval of transfer of any Evacuee Property under Section 10(2)(O) of the Act

(iii) Powers of transfer of cases under Rule 30-A of the Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 1950

2. This supersedes Notification No. 1(1)/Spl. Cell/79.SS II, dated 9-10-1979

[No 1(1)/Spl Cell/79-SS -II]
GOVIND JEE MISRA, Custodian General

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली 17 सितम्बर, 1980

का० आ० 2645—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियो की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और, (क) भारत सरकार, निर्माण, आवास और आपूर्ति मत्रालय की दिनाक 4 नवम्बर, 1961 की अधिसूचना सं० आ० स० 2601, जहां तक यह मध्य रेलवे के वरिष्ठ मडल इजीनियरो के सबध मे मद 1 से संबंधित है, (ख) रेल मत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनाक 16 सितम्बर, 1978 की अधिसूचना सा० आ० स० 2708, जहां तक यह पूर्व रेलवे के मंडल इंजीनियरो के सबध मे मद 3 से संबधित है, (ग) भारत सरकार निर्माण, आवास और आपूर्ति मत्रालय की 4 नवम्बर, 1961 की अधिसूचना सा० आ० सं० 2601, जहां तक यह उत्तर रेलवे के मडल अधीक्षको के संबध मे मद 3 से संबंधित है , (घ) रेल मत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 27 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना सा० आ० स० 3912 , (ङ) स्वास्थ्य परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय की दिनाक 11 जुलाई, 1970 की अधिसूचना सा० आ० स० 2344 जहां तक यह पूर्वोत्तर सीमा रलवे के मडल अधीक्षको के संबध मे मद (1) और 3(iii) से संबधित है, (च) भारत सरकार, निर्माण, आवास और आपूर्ति मत्रालय की दिनांक 4 नवम्बर, 1961 की अधिसूचना सा० आ० स० 2601, जहां तक यह दक्षिण रेलवे के मंडल अधीक्षको के संबंध मे मद 6 से सबंधित हैं , (छ) भारत सरकार, निर्माण, आवास और आपूर्ति मत्रालय की दिनांक 15 अप्रैल, 1967 की अधिसूचना सा० आ० स० 1294 जहां तक यह दक्षिण-मध्य रेलवे के मंडल अधीक्षको के संबध म मद (1) से सबंधित है, और (ज) भारत सरकार, निर्माण, आवास और आपूर्ति मत्रालय की दिनांक 4 नवम्बर, 1961 की अधिसूचना सां० आ० स० 2601, जहां तक यह पश्चिम रेलवे क मडल अधीक्षको क सबध म मद 8 से संबंधित है, के अतिक्रमण मे, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी तालिका के कालम (1) मे उल्लिखित अधिकारिया जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और आगे यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी सम्पदा अधिकारियो को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत प्राप्त शक्तियो का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यो का अनुपालन उक्त तालिका मे कालम (2) मे तदनुरूपी प्रविष्टि मे विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानो के संबंध मे अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओ के अंतर्गत करेगे ।

तालिका

अधिकारियो का पदनाम	सरकारी स्थानो की कोटियां तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
1 मडल रेलवे प्रबधक, मध्य रेलवे, बम्बई, भुसावल, नागपुर, जबलपुर झांसी और शोलापुर	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित मध्य-रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण मे परिसर।

1	2
2. मंडल इंजीनियर, पूर्व रेलवे, हावड़ा, आसनसोल, धनबाद, दानापुर, सियालदह और मुगलसराय।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्व रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
3. मंडल रेलवे प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद, फीरोजपुर, जोधपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नयी दिल्ली और बीकानेर।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित उत्तर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण मे परिसर।
4. मंडल रेलवे प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ, वाराणसी, सबलपुर और सोनपुर।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण मे परिसर।
5 वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, कटिहार, अलीपुरद्वार जंकशन और लमडिंग।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
6. मंडल रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण रेलवे, मद्रास, मैसूर, ओलवक्कोड, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और तिरुवनन्तपुरम।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत स्थित दक्षिण रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
7. मंडल रेलवे प्रबन्धक, दक्षिण-मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद (बड़ी लाइन), हैदराबाद (मीटर लाइन), विजयवाड़ा, हुबली और गुन्टाकल्लु।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत स्थित दक्षिण-मध्य रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
8. मंडल रेलवे प्रबन्धक, पश्चिम रेलवे, बम्बई, वडोदरा, रतलाम कोटा, जयपुर, अजमेर और भावनगर।	उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।

[फाइल सं० 69/डब्ल्यू 2/एलई/13]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th September, 1980

S.O. 2645.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of(a) Government of India, Ministry of Works, Housing, and Supply notification S.O. No. 2601, dated the 4th November, 1961 insofar as it relates to item 1 pertaining to the Senior Divisional Engineers of the Central Railway; (b) Ministry of Railways (Railway Board) notification S.O. No. 2708 dated the 16th September, 1978, insofar as it relates to item 3 pertaining to Divisional Engineers of Eastern Railway; (c) Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply notification S.O. No. 2601 dated the 4th November, 1961, insofar as it relates to item 3 pertaining to the Divisional Superintendents of Northern Railway; (d)Ministry of Railways (Railway Board) notification S.O. No. 3912 dated the 27th September, 1969; (e) Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development notification S.O. No. 2344 dated the 11th July, 1970, insofar as it relates to items 3(i) and 3(iii) pertaining to the Divisional Superintendents of Northeast Frontier Railway; (f) Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply notification S.O. No. 601 dated the 4th November, 1961 insofar as it relates to item 6 pertaining to the Divisional Superintendents of Southern Railway; (g) Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply notification S.O. No. 1294 dated the 15h April, 1967 insofar as it relates to item(i) pertaining to the Divisional Superintendents of South Central Railway; and(h) Government of India, Ministry of Works, Housing and Supply notification S.O. No. 2601 dated the 4th November, 1961 insofar as it relates to item 8 pertainig to the Divisional Superintendents of Western Railways, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officers of the Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties implosed on State Officers by or under the said Act, with the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
(1)	(2)
1. Divisional Railway Managers Central Railway, Bombay, Bhusawal, Nagpur, Jabalpur Jhansi and Sholapur.	Premises under the administrative control of the Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdication.
2. Divisional Engineers, Eastern Railway, Howarah, Asansol, Dhanbad, Danapur, Sealdah and Moghalsarai.	Premises under the administrative control of the Eastern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
3. Divisional Railway Managers, Northern Railway, Allahabad, Ferozpur, Jodhpur, Lucknow Moradabad, New Delhi and Bikaner.	Premises under the administrative control of the Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
4. Divisional Railway Managers North Eastern Railway, Izatnagar, Lucknow, Varanasi, Samastipur and Sonapur.	Premises under the administrative control of the North Eastern Railway situated within the local limists of their respective jurisdiction.
5. Senior Divisional Engineers, Northeast Frontier Railway, Katihar, Alipurduar Junction and Lumding.	Premises under the administrative control of the Northeast Frontier Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
6. Divisional Railway Managers, Southern Railways, Madras, Mysore, Olavakkot, Madurai, Tiruchchirapolly and Trivandrum.	Premises under the adminstrative control of the Southern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
7. Divisional Railway Managers, South Central Railway, Secunderabad (B.G.), Hyderabad (M.G.), Vijayawada, Hubli and Guntakal.	Premises under the adminstrative control of the South Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.

(1)	(2)
8. Divisional Railway Managers, Western Railway, Bombay, Vododara, Ratlam, Kota, Jaipur, Ajmer, and Bhavnagar.	Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[File No. 69/W-2/LE/13]

का० आ० 2646.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय की दिनाक 18-8-1964 की अधिसूचना सं०आ० सं० 2946 जहां तक यह सम्पदा अधिकारियों, दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर, बिलासपुर और वाल्तेरू के संबंध में मद 2, 3, और 4 से संबंधित है, के अतिक्रमण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारियो, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है और उनको यह निदेश देती है कि सम्पदा अधिकारियों को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत प्राप्त शक्तियो का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन उक्त तालिका के कालम (2) में तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओ की अंतर्गत करेंगे।

तालिका

अधिकारियों के पदनाम	सरकारी स्थानों की कोटिया तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमायें
1. सम्पदा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, खड़गपुर।	खड़गपुर मंडल के गार्डन रीच, शालीमार और संतरागाछी क्षेत्रों सहित आद्रा और खड़गपुर मंडलों की स्थानीय सीमाओ में स्थित दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।
2. सम्पदा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, बिलासपुर।	बिलासपुर, चक्रधरपुर और नागपुर मंडलों की स्थानीय सीमाओं में स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण मे परिसर।
3. सम्पदा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, वाल्तेरू।	वाल्तेरू और खोरधा रोड मंडली की की स्थानीय सीमाओं में स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर।

[फाइल स० 69/डब्ल्यू 2/एल०ई०/13]
के० बालचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड

S.O.2646 :—In excercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971, (40 of 1971), and in supersession of Government of India, Ministry of Works and Housing Notification S.O. No. 2946 dated the 18th August, 1964, insofar as it relates to items 2, 3 and 4 pertaining to the Estate Officers, South Eastern Railway, Kharagpur, Bilaspur and Waltair, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being gazetted officers of the Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act, with the local limits of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officers	Categories of Public premises and local limits of jurisdiction.
1. Estate Officer, South Eastern Railway, Kharagpur.	Premises under the administrative control of the South Eastern Railway situated within the local limits of Adra and Kharagpur Divisions including the areas of Garden Reach Shalimar and Santiagachi of Kharagpur, Division.
2. Eastate Officer, South Eastern Railway, Bilaspur.	Premises under the administrative control of the South Eastern Railway situated within the local limits of Bilaspur, Chakradharpur and Nagpur Division.
3. Estate Officer, South Eastern Railway, Waltair.	Premises under the administrative control of the South Eastern Railway situated within the local limits of Waltair and Khurda Road, Divisions.

[File No. 69/W-2/LE/13]
K. BALACHANDRAN, Secy. Railway Board.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1980

का० आ० 2647.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में यूनियन बैंक आफ इंडिया, टेक्सटाइल मार्किट ब्रांच, सुरत के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण, गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री आर० सी० इसरानी होंगे जिनका मुख्यालय अहमदाबाद मे होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण की न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूचित

क्या यूनियम बैंक आफ इंडिया, टेक्सटाइल मार्किट ब्रांच, सूरत के प्रबन्धतंत्र की लेजर मशीम के संचालन के कार्य के आबंटन की प्रणाली को दिसम्बर, 1978 से वरिष्ठता के आधार से चक्रानुक्रम के आधार पर परिवर्तित करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार है ?

[सं० एल०-12011/30/79-डी०-2(ए)]
एम० के० विश्वास, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 5th August 1980

S.O. 2647.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Union Bank of India, Textile Market Branch, Surat and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri R.C. Israni shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Union Bank of India, Textile Market Branch, Surat in changing the system of allotment of work of Ledger Machine Operation from seniority basis to rotational basis since December, 1978 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled and from which date ?

[No. L-12011/30/79-D.II(A)]
S. K. BISWAS, Desk Officer

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1980

का० आ० 2648.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 912, तारीख 21 मार्च, 1980 द्वारा तांबा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पहली अप्रैल, 1980 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ;

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पहली अक्तूबर, 1980 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं० एस-11017/4/79-डी० 1 (ए०)]
एल० के० नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 17th September, 1980

S.O. 2648.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 912 dated the 21st March, 1980, the Copper Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 1st April, 1980;

And whereas the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 1st October, 1980.

[No. S-11017/4/79-D. I. (A)]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 18th September, 1980

S.O. 2649.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947),the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial disputes between the employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of Messers Indian Iron and Steel Company Limited, Post Offices Bhaga, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1980.

BEFORE SHRI J. P. SINGH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) DHANBAD

Reference No. 17 of 1979

In the matter of an industrial dispute under S. 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur colliery of Messers Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, Distrit Dhanbad.

AND

Their workmen :

APPEARANCES:

On behalf of the employerss : Shri T.P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen : Shri B. Lal, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 1st September, 1980

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. L-20012/233/78-D. III (A) dated 12th April, 1979 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Noonodih-Jitpur colliery of Messers Indian Iron and Steel Company Limited, Post office Bhaga, District Dhanbad in dismissing Shri Surendra Singh, Stowing mazdoor from service with effect from 7th October, 1976, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. The parties were heard on the question as to whether the domestic enquiry held in this case was fair and proper since a preliminary point was raised to that effect. It was held by this Tribunal by an order dated 17-10-79 that the domestic enquiry was fair and proper. After that the case has been heard on merit.

3. On 6-9-76 Shri S. P. Mehra, manager, 16 Seam of Noono-dih-Jitpur colliery was on way to consult the Senior Medical Officer in the colliery dispensary. Shri Surendra Singh, the concerned workman met him and demanded that he should be put on the surface job. Shri Mehra told him that there was

no vacancy on the surface and expressed his inability to accede to his request. Shri Mehra then went to the dispensary. On way back from dispensary Shri Mohan, an Welfare Officer of the colliery gave him lift on his scooter. The workman happened to be on the way near the bunglow of the hospital doctor, stopped him and repected his demand. Shri Mehra again refused whereupon the concerned workman dragged him from the scooter and assaulted him with fists and slabs. Shri Mehra fell on the ground and his shirt was torn. Shri Mohan and some other employees who were near about saved Shri Mehra from further assault. The concerned workman threatened to kill Shri Mehra.

4. On the same day Shri Surendra Singh was issued charge-sheet for misconduct under Section 27(5) of the Standing Order and was suspended pending enquiry. He was asked to show cause within 48 hours of the receipt of the charge-sheet, but 15 days after the receipt of the charge-sheet he submitted his show-cause on 21-9-76. Shri P.K. Bhandari, Sr. Personnel Officer, Chasnalla colliery was entrusted with the enquiry. He started his enquiry on 24-9-76 and concluded it on 25-9-76. He submitted his report on the basis of which the concerned workman was dismissed from service.

5. I have already said that the enquiry was held to be fair and proper and we have now to consider the case on merit. Ext. M1 is the charge-sheet issued against Shri Surendra Singh. Ext. M2 is the order of dismissal under the signature of the Area Manager. A criminal case was also started under Section 353 and 323 I.P.C. He was convicetd by the Magistrate and sentenced to R.I. for one month under S.353 I.P.C. He was also convicted under Section 323 but no sentence was given. Ext. M3 is the judgement of the Magistrate. Ext. M5 is the enquiry proceeding and Ext. M6 is the enquiry report.

In the proceeding Shri S. P. Mehra, the manager of the colliery was examined and he gave details of the occurrance in which he was assaulted by Shri Surendra Singh. The Welfare Shri R. Mohan, who was present at the time of occurance gave an eye witness account of the occurance. One Shri Motilal Yadav had gone to the hospital for medicine and when he was returning he saw the occurance with his own eyes. Another witness Shri Mohar Singh was also returning from the hospital when he saw Shri Surendra Singh assaulting Shri Mehra. Dr. Gupta medical officer and examined Shri Mehra in his colliery office at about 10 A. M. and the injury report was marked Ext. M3 by the enquiry officer. There were six injuries of which two were bruises .

7. The concerned workman did not attend the enquiry and no witness was examined on his behalf. For all practical purposes, therefore, the enquiry had been ex-parte.

8. Shri Lal, Advocate appearing on behalf of the workman has said nothing with regard to the conclusions drawn by the enquiry officer from the facts and circumstances appearing in this case. His report is further supported by the judgement of the Judicial court regarding conviction under Section 353 and 323 I, P. C. Shri Lal tells me that there has been an appeal preferred in the Court of the Session Judge and therefore the matter is subjudice. At any rate if the management has accepted the report of the enquiry Officer which is based on correct apprisal of facts relating to the charges levelled against the concerned workman and punishment was awarded on that basis, the management cannot be said to have acted arbitrarily. It is true that the concerned workman was alleged to have assaulted the colliery manager whose duty it is to run the colliery. It will be a height of indiscipline on the part of the concerned workman to assault the colliery manager and to threaten to kill him simply because he refused to concede to his request to change his duty. There is no doubt that for the offence committed by the concerned wokman the only suitable punishment should be dismissal from service.

9. Shri Lal has argued before me that according to Standing Order No. 28 the approval of the owner, agent or Chief Mining Engineer of the company is required in every case of dismissal. In this case the Area Manager ordered the dismissal of the concerned workman from company's service with immediate effect through his letter Ext. M2. Ext. M2 further mentions that the approval of the Chief Executive (Collieries) had been obtained before issue of that order. Shri Lal has argued that neighier the Area Manager nor the Chief Executive (Collieries) have been shown to have the powers of onwner, agent or Chief Mining Engineer as provided under Rule 28 of the Standing Order. In this case a petition was filled on behalf of the concerned workman on 7-7-80. On behalf of the management a rejoinder was filed on 21-7-80 including a photostate copy of a letter dated 28th June, 1974 by the Indian Iron & Steel Company Ltd. It was a letter addressed to the Director General, Mines Safety, Dhanbad, by the Chief Executive (Collieries). The letter is to the effect that Shri R. K. Prasad, First Class Mines Manager certificate holder had been appointed as an Agent under the Mines Act of Noonodih-Jitpur colliery w.e.f. 1st July, 1974. It has been also argued that the Chief Executive (Collieries) is equivelent to the Chief Mining Engineer. It was further asserted that the designation of the Agent was changed to Area Manager for the purpose of administration. On 30-7-80 another petition was filed on behalf of the workman that Shri R. K. Prasad, the Area Manager passed the order of dismissal as Area Manager after obtaining approval of the Chief Executive (Collieries) and as such he did not exercise the said power as Agent. There was a rejoinder filed by the management to this petition also on 28-8-80. Since all these matters came up after the award was reserved, the parties lawyers were heared from time to time which caused some delay in delivering this judgement. Now it has been rightly argued on behalf of the management that when this reference was made and the parties were asked to file there written statement, the dismissal order was not challenged on the ground that the Area Manager who passed the dismissal order had no authority to do so. In fact this plea was taken at the time when Shri Lal, Advocate was arguing the case on babehalf of the workmen. The management after that has shown by the letter of the Chief Executive (Collieries) of the IISCO that Shri R. K. Prasad who issued the dismissal letter was the Agent within the meaning of the Standing Order No. 28. The Agent has the power of dismissal under Standing Order No. 28 and he exercised his authority in issuing the dismissal order. It is true that in Ext. M2 he had taken the approval of the Chief Executive (Collieries). The management has not established that the Chief Executive (Collieries) is equivelent to the Chief Mining Engineer who has the equal power to issue dismissal order under Standing order No. 28. But Shri R. K. Prasad who is shown to have the power of the Agent under Standing Order No. 28 has the concurent power with the Chief Engineer to record an order of dismissal. I see no legal lacuna when Shri R. K. Prasad obtained the approval of the Chief Executive (Collieries) before issuing that order. So, the mere mentioned that he took the approval of the Chief Executive (Collieries) will not go to minimise the effect of the dismissal order issued by him under Ext. M2.

10. Having considered all aspects of the case, I hold that the action of the management of Noonodih-Jitpur colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad in dismissing Shri Surendra Singh,

Stowing Mazdoor from service with effect from 7th October, 1976, is justified. Consequently, the workman is entitled to no relief.

This is my award.

J. P. SINGH,
Presiding Officer,
[No. L-20012/233/78-D. III (A)]
S. H. S. IYER, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1980

का० आ० 2650—व्यास सतलुज लिंक परियोजना के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद में, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कानपुर और मध्यस्थ ने 10 अक्तूबर, 1974 को पंचाट दिया ;

और केन्द्रीय सरकार की राय में इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट प्रश्न पर उपर्युक्त पंचाट की व्याख्या के बारे में एक सन्देह उत्पन्न हुआ है और केन्द्रीय सरकार इस प्रश्न को व्याख्या के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को, न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या दिनांक 10-10-1974 का मध्यस्थ का पंचाट, जो दिनांक 9-11-1974 के भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में पृष्ठ 3162 पर प्रकाशित हुआ है; कर्मकारों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लाभों का कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में उनके पुनः तबादले की तारीख से हकदार बनाता है या उस तारीख से हकदार बनाता है जब से कर्मचारी भविष्य निधि योजना इन प्रतिष्ठानों पर लागू की गई थी।"

[संख्या एल०-42011/10/77-डी०-II (बी०)]
एस० एस० भल्ला, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1980

S. O. 2650.—Whereas in an industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Sutlej Link Project, and their workmen, the Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur and Arbitrator gave an award on the 10th October, 1974;

And, Whereas, in the opinion of the Central Government a doubt has arisen as to the interpretation of the said award on the question specified in the Schedule hereto annexed, and the Central Government considers it desirable to refer the question for interpretation;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 36-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether the award of the Arbitrator dated 10-10-74 and published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii) dated 9th November, 1974 at page-3162 entitles the workers to the benefit of Employees' Provident Fund Scheme from the date of their retransfer to the establishments covered by the Factory Act or from the date from which the Employees' Provident Fund Scheme was made applicable to these establishments."

[No. L-42011 (10)/77-D. II (B)]
S. S. BHALLA, Desk Officer

New Delhi, the 26th September, 1980

S. O. 2651:—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. M.S. Sawhney & Sods, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1980.

BEFORE SHIR JITENDRA NARAYAN SINGH, PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2., BOMBAY

Reference No. CGIT-2/10 of 1979.

(Original Reference No. CGIT-2/16 of 1969)

PARTIES :

Employers in Relation to Messrs M/s. Sawhney and Sons

AND

Their Workmen

APPEARANCES :
For the Employers — Shri P. R. Pai, Advocate.
For the Workmen — No appearance

Industry : Stone Quarry

State : Maharashtra

Bombay, dated the 29th August, 1980.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, (Department of Labour and Employment) in exercise of the powers conferred under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute as mentioned below by Order No. 36/23/69-LRIV dated 7-10-1969:—

"Whether the action of the management of Messrs M. S. Sawhney and Sons, Chandivali, Bombay in terminating the services of the following 12 female workers with effect from the dates noted against each was justified? If not, to what relief the workers concerned are entitled ?

Name of the Female workers	Date of termination
1. Smt. Trivenibai Samrath Suryavanshi	11-10-1968
2. Smt. Hirabai Govind Kamble	27-9-1968
3. Smt. Gangubai Lingu Kamble	16-8-1968
4. Smt. Sunpabai Sahebrao Awade	11-10-1968
5. Smt. Chandrabaghai Kishen Shinde	11-10-1968
6. Smt. Giniambai Govind Shinde	27-9-1968
7. Smt. Vithabai Kashiram Shinde	11-10-1968
8. Smt. Laxmibai Niverthi Gaikwad	27-9-1968
9. Smt. Subadrabai Vaiznath Bhosle	27-9-1968
10. Smt. Rahibai Tulsiram Kamble	11-10-1968
11. Miss. Nagarbai Jalba Gaikwad	11-10-1968
12. Smt. Narsabai Rathunath Kamble	11-10-1968

Both the parties filed their written statement and the case was heard by my predecessor in office Shri N K. Vani, who by his Award dated 9-9-1974 passed the following order —

"(ii) It is hereby declared that the action of the management of M/s Sawhney & Sons, Chandivali Bombay in terminating the services of the 12 females workers w e f. the dates noted against each in the schedule of the reference was not justified and that they are entitled to reinstatement with continuity of service and that each one of them is entitled to back wages w e f 1st April, 1974

(i) Award is made accordingly.
(iii) No order as to costs"

As against this Award the management as well as the workmen went in revision application before the Hon'ble High Court of Bombay On hearing the parties the Hon'ble High Court were pleased to pass the following order —

"For the reasons stated in the accompanying judgement the Court rejects the petition filed by the employer challenging the award in the matter of reinstatement The Court, however, sets asside the award of the Tribunal with regard to back wages and remands back the matter to the Tribunal for the limited purpose of ascertaining whether they are entitled to the back wages for the entire period from the date of termination till reinstatement or whether the back wages should be only for a part of the period if they were gainfully employed, or not at all.

The Court directs the Tribunal that if evidence is already on record it shall make an award on the material already on record. The Court further directs that if the parties choose to lead additional evidence, the Tribunal shall record additional evidence and then give its award".

On receipt of the record from the Hon'ble High Court the office issued notices to both the parties for hearing The management appeared but the Union remained absent. The notice was sent to them on the address last known by the office but it was returned unserved The management was then directed to serve the notice on the Union. The management filed affidavit before the Tribunal on 30-7-1980 stating that a copy of the notice was displayed at the workspot with the intimation of the date of hearing. Another notice showing the adjuourned date of hearing was also pasted on the notice board but in spite of it the workmen have not appeared Thus the notice was served at the place of working of the workers also.

In order however to be more specific the Tribunal ordered a fresh notice to be issued to the Union according to the address as mentioned in the order of reference and accordingly a fresh notice was issued on the old address which has been duly received on behalf of the Union but in spite of it the Union has not appeared.

In the circumstances there was no alternative but to decide the issue on the evidence on record.

The management has filed another affidavit on 30-7-1980 stating that the concerned workmen 12 in number are not working with them. It is also stated that these workmen are gainfully employed from the date shown against their names in the affidavit in the neighbouring mines and are earning their livelihood It is further mentioned that these workmen have been seen by the management going for their work and it has also been confirmed by further enquiry The affidavit further says that for the said reason the concerned workmen are not appearing before this Tribunal It is therefore submitted that the concerned workmen are not entitled to any back wages

As against this I find from the record that all the workmen stated in their deposition that they were unemployed and were not getting work elsewhere In their cross-examination there is no suggestion on behalf of the management regarding the place where they were employed nor there is any suggestion that they are employed elsewhere In view of the evidence of the workmen it was the duty of the management to adduce evidence or give details of the employers under whom the concerned workmen were/are working In the affidavit no such details have been given. It is simply stated that these workmen are gainfully employed from the dates shown in the affidavit in the neighbouring mines and are earning their livelihood If the management know on enquiry or otherwise that the concerned workmen are working in the neighbouring mines they should have specified the names of the mines where the concer ned workmen were/are working, but this has not been done

In the circumstances it must be held that these workmen are unemployed from the date of their stoppage from work by the management and hence they are entitled to back wages from the date of termination of their service till the date of reinstatement

I give may award accordingly

No Order as to costs.

Sd/-

JITENDRA NARAYAN SINGH,
Presiding Officer

[No 36/23/67-LR. IV/D III (B)]

New Delhi, the 27th September, 1980

S O. 2652 In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Manganese Ore Indian Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1980

BEFORE SHRI A G QURESHI, M A LL B ,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR
COURT, JABALPUR M P

Case No. Cgil/LC(R)(33) of 1979

PARTIES :

Emplo yers in relation to the management of Mansar Manganese Mine of M/s. Manganese Ore India Limited, 3, Mount Road Extension, Nagpur and their workman, represented through Samyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITUC) Parwana Memorial Building, 44-Kingsway, Nagpur (M S)

APPEARANCES :

For workman —Shri P K Thakur, Advocate
For Management —Shri P S. Nair, Advocate

INDUSTRY :

Manganese Ore India limited—District Nagpur, (M S)

AWARD

The Central Government in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide order No L-27011/3/78-D. III(B), dated 28th November, 1979

"Keeping in view the actual work performed by Shri Ishwardas, S/o Laxman, Couplingman Helper (Unskilled), Mansar Manganese Mine of Manganese Ore India Limited, Nagpur whether he is justified in demanding the category of semiskilled workman with attendant benefits with effect from 4 3.1974? If so, what relief is the said workman entitled to ?"

2. The case of the Union in short is that Shri Ishwardas has been working as a Couplingman Helper in the Mansar Mine of the Manganese Ore India Ltd. Nagpur from the date of his appointment i.e. 22-7-1966. On 4.3. 1974 the management issued a letter of authorisation bearing No. 154 under the Metalliferrous Mines Regulations (MMR) asking the workman to work as per requirements of the Regulation No. 39 of the MMR 1961. Again on 18-8-1978 an authoirisation, as issued earlier, was issued. By both the aforesaid authorisations the workman was appointed under Regulation 39 of the MMR 1961 as a competent person for carrying out the duties of couplingman at Mansar Mines. The workman has been continuously carrying out the duties assigned to him which cannot be characterised as unskilled. The other workmen doing the same type of job were also placed in the Semiskilled Category, but Ishwardas was not placed in the Semiskilled Category. Therefore, he is entitled to be placed in semiskilled category with effect from 4-3-1974 with all the attendant benefits.

3. The management has resisted the claim of the Union on the ground that Shri Ishwardas was appointed as an unskilled worker and was doing the duties of pushing and cleaning of the tubs which did not require any skill. The Mansar Mine is an open cost mine. Manganese Ore are produced at different places and then loaded in tubs by that workman. Such loaded tubs are pushed by the individual workers from their respective place of work and brought to the haulage point and left there. These tubs are further pushed and coupled by the couplingman with the help of one or two other workers. After this the tubs are pulled up through haulage to the top of the pit where they are uncoupled by another couplingman. The tubs are then carried away by the labourers employed for pushing the tubs. The aforesaid process indicates that the labourers engaged on this work are not required to do any job which may require any skill. The job is totally unskilled and can be managed by any labourer without any experience or training of any nature. Therefore, such labour cannot be categorised as semiskilled workers. Shri Ishwardas is also one of the labourers engaged in the aforesaid work.

4. According to the management, promotion from unskilled to semiskilled category is based on seniority-cum-merit. This has to be done by a D.P.C. considering all the aspects of each case. Promotion being purely a managerial function cannot be interfered with, without a proof of malafide or victimisation. There is no malafide or victimisation in the instant case. Therefore the claim of the Union is baseless.

5. The management has not adduced any evidence. The Union has examined the concerned workman Shri Ishwardas. He has stated on oath before me that he was posted in Mansar Mines as a Helper Coupling Mazdoor. Earlier he had raised a demand through the Union for being promoted as a semiskilled workman with effect from 4-3-1974, but the management has now promoted him as a Coupling Mazdoor and placed him in the Semiskilled category from 24-1-1980. He is satisfied with the promotion and does not want to press his demand for being promoted with effect from 4-3-1974. He has also stated that he abandons his claim for seniority and other benefits for the period between 4-3-1974 to 24-1-1980. He has now no dispute with the management.

6. In view of the above statement of the concerned workman himself, there remains no dispute in existence and consequently the workman is not entitled to any relief. An award is given accordingly.

14-8-1980 (A.G. QURESHI)
Presiding Officer

[No. L-27011/3/78-D.III(B)
A. K. ROY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980